दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 16 ▸ अंक : 10 ▸ गाजियाबाद, अक्टूबर, 2020 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 04 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज..P-4

कोरोना लाइव

6,695,118	5,666,925	103,654	35,803,090
मामले (भारत)	मरीज ठीक हुए	कुल मौतें	मामले (दुनिया)

यूपी में बिजली विभाग का निजीकरण टला

कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे

लखनऊ। बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। हड़ताल से उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में हाहाकार मच गया था। कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन बद से बदतर हुए हालात के मद्देनजर यूपी सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल तीन महीने के लिए टाल दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। कहा जा रहा है कि अब इन तीन महीनों कोई न कोई समाधान खोज लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार और बिजली कर्मचारी संयुक्त परिषद के बीच पांच बिंदुओं पर सहमति बनी है। तय हुआ है कि फिलहाल बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होगा। यदि कभी निजीकरण हुआ तो पहले बिजली विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों की सहमति ली जाएगी। इसके अलावा अगले 15 जनवरी 2021 तक लगातार समीक्षा होगी। इसके साथ ही विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने, कंपनियों का घाटा कम करने, राजस्व वसूली बढ़ाने और बिलिंग सिस्टम को दुरुस्त करने में भी बिजली कर्मचारी संयुक्त परिषद अपनी भूमिका निभाएगा। इस बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद बिजली कर्मचारी संयुक्त परिषद ने हड़ताल खत्म की घोषणा की। इसके बाद सभी कर्मचारी काम पर लौट गए। हालांकि हड़ताल खत्म होने के बाद भी यूपी के कई शहरों में देर रात तक बिजली नहीं आई थी।

बिजली ठप होने की वजह से पानी की आपूर्ति भी बंद रही। उपभोक्ताओं ने दो दिन से दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी न होने की शिकायत की। प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि उन्हें रात-रात भर जागना पड़ रहा है। नींद पूरी नहीं हो रही। बिजली पानी ठप होने की वजह से दिनचर्या के काम निपटाने में भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति को सामान्य करने की मांग की। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार का आज दूसरा दिन था। बिजली कर्मचारियों ने सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को ही ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से समझौते का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर इनकार कर दिया था। निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से कहा था कि अगर उनकी मांगे न मानी गईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आम जनता की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। माना जा रहा है कि सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये ये फैसला लिया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में हाहाहार मच गया था। हड़ताल वापस होने की सूचना ने उन्हें बड़ी राहत दी है। बिजलीकर्मियों के कार्य बहिष्कार के कारण सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा सहित तीन दर्जन से अधिक मंत्रियों और करीब 150 विधायक, विधान परिषद सदस्यों के सरकारी आवास सहित राजधानी की बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। वीवीआईपी इलाकों में बिजली गुल होने से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से लेकर शासन स्तर तक हड़कंप मच गया, लेकिन बिजली अभियंताओं ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने से मना कर दिया। आनन-फानन मध्यांचल निगम के एमडी सूर्यपाल गंगवार ने निदेशक (तकनीकी) सुधीर कुमार को कूपर रोड उपकेंद्र भेजा। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वैकल्पिक स्त्रोत से बिजली सप्लाई बहाल हुई। लेसा के राजभवन डिवीजन के अंतर्गत कूपर रोड उपकेंद्र में सुबह करीब 11 बजे बिजली सप्लाई ठप हो गई। इससे विक्रमादित्य मार्ग, माल एवेन्यू, गुलिस्तां कॉलोनी, महिला विधायक आवास, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी सहित कई वीआईपी इलाकों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। इससे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्या, मोहसिन रजा, मुकुट बिहारी वर्मा, अनिल राजभर सहित तीन दर्जन से अधिक मंत्रियों के सरकारी आवास की बिजली गुल हो गई।

> गोमतीनगर ट्रांसमिशन से कूपर रोड उपकेंद्र को आने वाली विद्युत लाइन ब्रेकडाउन हो गई थी। इससे कई मंत्रियों, विधायकों सहित कई जनप्रतिनिधियों की बिजली सप्लाई बाधित हुई थी। जिसके बाद निदेशक (तकनीकी) को उपकेंद्र भेजकर वैकल्पिक स्त्रोत से बिजली सप्लाई चालू कराई।
>
> -सूर्यपाल गंगवार, प्रबंध निदेशक, मध्यांचल निगम

इसके अलावा 150 से अधिक विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व मंत्री, न्यायाधीश व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बगैर बिजली के रहना पड़ा। साथ ही मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम, समाजवादी पार्टी कार्यालय, कांग्रेस मुख्यालय, वीआईपी गेस्ट हाउस में बिजली सप्लाई न होने से काफी दिक्कत हुई।

हिंडन एयरबेस पर जंगी विमानों ने दिखाए करतब

गाजियाबाद। भारतीय वायु सेना 8 अक्टूबर को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इसी कड़ी में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन हिंडन स्थित एयरफोर्स स्टेशन में वायुवीरों ने किया। भारत वार्षिक वायु सेना दिवस पर अपनी वायु शक्ति दिखाता है। यह वर्ष विशेष होगा क्योंकि भारतीय वायु सेना दिवस परेड में नए राफेल लड़ाकू विमान को शामिल करेगा। भारत की वायु शक्ति को प्रमुख बढ़ावा देने के लिए पांच राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। वायुसेना दिवस 1932 में भारतीय वायुसेना द्वारा स्थापित किए गए दिन को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। एयरचीफ मार्शल एसकेएस भदौरिया के अनुसार राफेल हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस 4.5 पीढ़ी, ट्विन-इंजन ओम्नीरोले, वायु वर्चस्व, अंतर्विरोध, हवाई टोही, जमीनी समर्थन, गहराई से हड़ताल, जहाज-रोधी और परमाणु निवारक लड़ाकू विमान है। एयरफोर्स- डे को लेकर वायुसेना स्टेशन हिंडन में मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से मीडियाकर्मियों के अलावा वायुसैनिकों के परिजनों ही फुल ड्रेस रिहर्सल का आनन्द ले सके। स्कूली बच्चें और अन्य लोग इस बार जंगी जहाजों का का रोमांच नही देख पाए। इस बार आसमान में लड़ाकू विमान राफेल, चिनूक, तेजस और सारंग से भारतीय जांबाजों ने बिना दर्शकों के ही करतब दिखाए। सुबह आठ बजे से ही आसमान में भारतीय विमानों की गड़गड़ाहट ने आसपास के इलाकों में रोमांच पैदा कर दिया। लोग अपनी-अपनी छतों, बालकनी में निकलकर इस अद्भुत नजारे का लुत्फ लेने लगे। आठ अक्तूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना के तहत हिंडन वायुसेना स्टेशन में यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाजा इस दिन से लग जाता है। मंगलवार को वायुसेना के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल में कई ऐसे करतब दिखाए, जिसकी गरज आसमान में देखी गई और देशवासियों ने इसका रोमांच अपने दिलों में महसूस किया। जवानों ने वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन कर सभी को रोमांचित कर। पिछली बार रिहर्सल में अपाचे और चिनूक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे थे। तो इस बार राफेल पर सभी की नजर टिकी रही।

हिंडन एयरबेस के पास जिन लोगों के घर हैं उन्होंने तो राफेल का दीदार बहुत ही पास से किया और परिजनों से सोशल मीडिया के जरिए इस खुशी का इजहार किया। छोटे-छोटे बच्चे भी राफेल को देखकर उसकी गरज सूनकर खुशी से झूम उठे और राफेल-राफेल चिल्ला कर कूदने लगे।

इस मौके पर जमीन पर जवानों की कदमताल हुई जबकि आकाश में सारंग, सूर्य किरण और पैराजंपर्स के करतब भी हुए। हजारों फिट ऊंचाई से पैराशूट लेकर जवानों ने उड़ान भरी तो वहीं सारंग व चिनूक के साथ स्वदेशी हल्के विमान तेजस की भी धमक नीले गगन में देखी गई। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में हर वर्ष हजारों दर्शकों के बीच फुल ड्रेस रिहर्सल देखने की व्यवस्था होती थी, मगर इस बार कोरोना महामारी की वजह से सभी प्रवेश से दूर रहे। इन सभी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क व सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई थी।

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

CATEGORY OF WORKERS	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING: U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
				MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/20 TO 30/09/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		1/3/2019	1/7/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I	BASIC+DA ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8625.00	10086.03	10574.06	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8776.83	9024.24	8331.00
SEMISKILLED	9487.50	11075.65	11631.46	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9556.83	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9475.43	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9949.19	*
SKILLED	10627.50	12295.73	12688.87	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10453.83	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10446.65	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10969	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11485.83	11517.45	*

जमीन माफियाओं को संरक्षण दे रहे है के के शर्मा

-उद्योग विहार (अक्टूबर 2020)-

गाजियाबाद। महापौर के पति केके शर्मा जहां अभी तक निगम एवं सरकारी जमीनों पर खरीद फरोख्त के बढते खेल को लेकर अभी तक ओम त्यागी तथा रविवर्मा को लगातार कटघरे में खडा कर रहे थे। पहली बार ओम त्यागी और रवि वर्मा संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आए और खुला आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर पति केके शर्मा ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे है जो किसान के फर्जी कागजों के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त करते है। जिनके खिलाफ बाकायदा नगर के द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज करायी गई है। ये खेल निगम के संपत्ति विभाग से मिलीभगत से किया जा रहा है। ओम त्यागी ने दावा किया उनके अपने प्रयास से ही मामला हाई कोर्ट में है तथा आवश्यकता पडने पर सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी। इस बीच शांति नगर में मकान तोडे जाने से प्रभावित लोगों को हर संभव सहयोग देने की मांग उठायी गई। नवयुग मार्केट में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान ओम त्यागी ने कहा कि महापौर पति ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे है जिनके द्वारा खुद को राजा राम बताते हुए फर्जी तरीके से आगरा से एटार्नी तैयार करायी गई और इस एटार्नी के माध्यम से जमीन को बेच दिया गया। जो मूल किसान था, उसे प्रकरण की भनक नहीं लगने दी गई।

छह बीघा शांति नगर की इस जमीन की आड में सरकारी जमीन बेचने वाले वह लोग है जो हाल में केके शर्मा के संवाददाता सम्मेलन के दौरान मौजूद थे। जिनके खिलाफ उनके प्रयास से ही 2015 में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज करायी गई। मूल किसान को एक इंच जमीन के मुआवजे का लाभ नहीं मिला। इस दौरान संवाददाताओं के सवालों के जबाव में ओम त्यागी ने दावा किया कि उनके द्वारा कोई अनाधिकृत कालोनी नहीं काटी गई, केवल किसान की जमीन खरीद खेती के लिए बेचने का प्रयास किया गया। ये भी दावा किया कि उनके केके शर्मा और अनिल स्वामी से व्यक्तिगत संबंध है।

इस बीच रवि वर्मा ने दावा किया कि उन्हें केके शर्मा बेवजह भू माफिया बता रहे है। नंद ग्राम से लगे साईं एन्कलेव में जो उनके द्वारा भूखंड खरीदा गया था,जमीन को अपनी बताते हुए महापौर पति केके शर्मा कब्जा करना चाहते है। 7 फरवरी 2020 को बाउंसर लेकर मौके पर पहुंच गए थे और निगम के सरकारी बुलडोजर से चारदीवारी तोड दी थीं।

बाकायदा पुलिस में उनके द्वारा न केवल तहरीर दी गई बल्कि तहसील दिवस में भी उनके द्वारा मामले को उठाया गया था। इस बीच से भी दावा किया गया कि उनके पास दस से ज्यादा ऐसे बेनामों की प्रति है, जिन पर महापौर पति के फोटो के साथ उनके हस्ताक्षर है। ये भी आरोप लगाया कि निगम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को महापौर के द्वारा अंधेरे में रखने का काम किया गया।

ओम त्यागी और रवि वर्मा ने खुलकर महापौर पति पर लगाए गंभीर आरोप

चुनाव आयोग को अंधेरे में रखा आशा शर्मा ने

महापौर के पति एवं सामाजिक कार्यकर्ता केके शर्मा के खिलाफ रखे गए संवाददाता सम्मेलन के दौरान रवि वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर आशा शर्मा के द्वारा निकाय चुनाव के दौरान नामांकन प्रक्रिया के वक्त तथ्य छुपाते हुए चुनाव आयोग को अंधेरे में रखने का काम किया गया। महापौर पद के लिए जिस वक्त आशा शर्मा के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया गया उस दौरान आशा शर्मा के खिलाफ थाना सिहानी गेट में एक मामला दर्ज था, जो कि मौजूदा में भी माननीय अदालत में विचाराधीन है, इसका नामांकन के दौरान उल्लेख नहीं किया गया। श्री वर्मा ने कहा कि तमाम तथ्यों को चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा।

जेईई एडवांस परीक्षा : देश में तीसरी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम किया रोशन

-उद्योग विहार (अक्टूबर 2020)-

गाजियाबाद। आयुध निमार्णी निवासी वैभव राज ने प्रथम प्रयास में जेईई एडवांस की परीक्षा में देश में तीसरी रैंक हासिल करके क्षेत्र व अपने माता- पिता का नाम रोशन किया है। वैभव की सफलता पर उसके माता-पिता ने खुशी प्रकट की है। वैभव कंप्यूटर क्षेत्र में शोध करके देश सेवा करना चाहते हैं।

मूलरूप से बिहार के बेगूसराय निवासी सुनील कुमार राय रक्षा मंत्रालय के क्वालिटी एशोरेंस विभाग में सीनियर सेक्शन आफिसर के पद पर कार्यरत हैं। इस दिनों व मुरादनगर स्थित आयुध निमार्णी में तैनात हैं। सुनील कुमार के परिवार में उनकी पत्नी सुधा व दो बेटे विशाल व वैभव हैं। सोमवार को घोषित हुए जेईई एडवांस के परिणाम में वैभव ने परीक्षा में देश में तीसरी रैंक हासिल की है। परिणाम की जानकारी मिलते ही वैभव के परिवार में बधाई देने वालों का तांता लग गया। वैभव के पिता सुनील राय ने बताया कि वैभव हाईस्कूल से ही कोटा में रहकर कोचिंग कर रहा है। इसी वर्ष इंटर की परीक्षा में भी वैभव ने 99 फीसद अंक के साथ उच्च रैंक हासिल की थी।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.
❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)
http://www.legalipl.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र
Editorial

E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, अक्टूबर, 2020

सम्पादकीय

चुनौती और रणनीति

सत्येन्द्र सिंह

यह खबर निश्चित ही राहत देने वाली है कि अगले साल जुलाई तक देश के पच्चीस करोड़ लोगों को कोरोना का टीका मिल जाएगा। अभी तक तो यह सिर्फ उम्मीद ही व्यक्त की जा रही थी कि अगले साल के मध्य तक टीका आ सकता है, लेकिन अब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा इसका एलान किया है। इससे अब लोगों में इतना भरोसा तो बनेगा कि जल्दी ही कोरोना का टीका आने वाला है और हम महामारी को काबू कर सकेंगे। भारत में कोरोना से अब तक एक लाख लोग मारे जा चुके हैं और संक्रमितों का आंकड़ा छियासठ लाख के पार निकल चुका है। हालांकि अब संक्रमितों के सुधार की दर बढ़ रही है और संक्रमण से होने वाली मौतों की दर में भी कमी आ रही है, फिर भी खतरा बढ़ने का अंदेशा ज्यादा है क्योंकि चरणबद्ध तरीके से पूर्णबंदी हटा लिए जाने के बाद लोगों की आवाजाही जोर पकड़ने लगी है। इससे संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ रहा है। ऐसे में जितनी जल्दी टीका आएगा, उतना ही हम महामारी से अपने को बचा पाने में सक्षम हो पाएंगे। संकट की गंभीरता को देखते हुए भारत ने टीका बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं, देश में कई जगह टीकों के परीक्षण चल रहे हैं और सुखद संकेत तो ये हैं कि ज्यादातर मामलों में परीक्षण सफल रहे हैं। इसलिए जुलाई तक टीका आ जाने को लेकर अब कोई संशय बाकी नहीं रहना चाहिए। टीका तैयार करना जितना जटिल और चुनौतीभरा काम है, उससे कहीं ज्यादा कठिन उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि टीके की जरूरत सबको है, पर यह भी संभव नहीं है कि एक साथ इतने टीके आ जाएं कि पूरे देश के लोगों को लगा दिए जाएं। हालांकि नीति आयोग की एक उच्चस्तरीय समिति टीके के उत्पादन, रखरखाव, आपूर्ति, वितरण और प्राथमिकता से संबंधित सारे बंदोबस्त देखेगी और इसके लिए अभी से व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्यों से टीकाकरण की प्राथमिकता तय करने को कहा गया है। जिन राज्यों में हालात ज्यादा गंभीर हैं, वहां टीकाकरण का अभियान भी तेज रखना होगा। अभी तक का अनुभव यह बता रहा है कि कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा अस्पतालकर्मियों और पुलिस बल को जूझना पड़ा है। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों व अन्य कर्मियों के संक्रमित होने के मामले तेजी से बढ़े हैं और अब तक करीब चार सौ डॉक्टर कोरोना संक्रमण से मारे जा चुके हैं। पुलिस बल को भी जिस तरह के मुश्किल हालात में काम करना पड़ा है, उसी का नतीजा रहा कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी संक्रमण शिकार हुए। ऐसे में सबसे पहले टीका उन लोगों को लगेगा जो कोरोना योद्धा के रूप में मोर्चे पर डटे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। अगर अस्पतालकर्मी ही संक्रमित होते रहेंगे तो लोगों को कौन बचाएगा! टीके की मांग और आपूर्ति में लंबे समय तक भारी अंतर बना रहेगा, क्योंकि इसके उत्पादन में अभी वक्त लगेगा। अभी यह साफ नहीं है कि कौन–सी कंपनी कितना उत्पादन कर जरूरत पूरी कर पाएगी। जिन राज्यों में संक्रमण की मार पहले ही से ज्यादा है और जहां अब महामारी फैलने का खतरा कई गुना बढ़ रहा है, वहां लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है। कहने को देश के कुछ राज्यों में सामुदायिक संक्रमण के हालात हैं।

हाथरस प्रकरण ने समाज को झकझोरा, लेकिन क्या महिलाओं की स्थिति पर कोई फर्क पड़ेगा ?

दरिन्दों एवं वहशियों के चलते एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर गैंगरेप और भीषण यातनाओं का शिकार हुई यूपी के हाथरस जिले की 19 साल की दलित लड़की ने 15 दिनों तक मौत से जूझने के बाद मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस जघन्य, वीभत्स एवं दरिन्दगीपूर्ण गैंगरेप कांड से न केवल समूचा देश अशांत एवं शर्मसार हुआ है बल्कि कलंकित भी हुआ है। एक बार फिर नारी अस्मिता एवं अस्तित्व को नौंचने वाली इस घटना ने हमें झकझोर दिया है। यह त्रासद घटना बता रही है कि देश में लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। समूचे देश को करुणा–संवेदनाओं में डुबोने वाली इस घटना ने अनेक सवाल फिर से खड़े कर दिये हैं।

दिल्ली के निर्भया मामले के बाद जैसी जनक्रांति देखने को मिली थी, उससे यह उम्मीद बंधी थी कि अब शायद देश में महिलाओं को इस तरह की त्रासदियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन बलात्कार कानूनों की सख्ती के बावजूद ना बलात्कार रुके, ना दरिन्दगी, ना ही महिलाओं की हत्याएं। हाथरस की बेटी से दरिन्दगी हुई, इसकी पुष्टि उसकी मौत से होती है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और जीभ काटी गई। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों का जैसे सिलसिला चल पड़ा है। इस राज्य को महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य में शामिल कर दिया गया है। यह राज्य लम्बे समय से अपराध का गढ़ रहा है, यहां की पुलिस एवं प्रशासन भ्रष्ट एवं अराजक रहा है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इन अपराधी मानसिकताओं पर नियंत्रण पाने की कोशिशें हो रही हैं।

बेटी तो बेटी होती है, हाथरस की दलित बेटी भी बेटी ही है, भले उसे व्यक्तिगत रूप से कम ही लोग जानते रहे होंगे, लेकिन वह दरिन्दगी के 15 दिन तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के बाद अंततः वह हार गयी। उसकी दर्दनाक दास्तान ने देश की करोड़ों महिलाओं की वेदना को मुखर ही नहीं किया है बल्कि वह समाज को फिर सोचने को मजबूर कर गई। हाथरस की यह क्रूर एवं अमानवीय घटना महाभारतकालीन उस घटना का नया संस्करण है जिसमें राजसभा में द्रौपदी को बाल पकड़ कर खींचते हुए अंधे सम्राट धृतराष्ट्र के समक्ष उसकी विद्वत मंडली के सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास हुआ था। इस वीभत्स घटना में मनुष्यता का भद्दा एवं घिनौना स्वरूप सामने आया है। एक बार फिर अनेक सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर कितनी बालिकाएं, कब तक ऐसे जुल्मों का शिकार होती रहेंगी। कब तक अपनी मजबूरी का फायदा उठाने देती रहेंगी। दिन–प्रतिदिन देश के चेहरे पर लगती इस कालिख को कौन पोछेगा? कौन रोकेगा ऐसे लोगों को जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, नारी को अपमानित करते हैं।

इन ज्वलंत सवालों के उत्तर हमने निर्भया के समय भी तलाशने की कोशिश की थी। लेकिन इस तलाश के बावजूद इन घटनाओं का बार–बार होना दुःखद है और एक गंभीर चुनौती भी है। इस मौत ने गैंगरेप जैसे अपराध से निपटने में प्रशासनिक और पुलिस तंत्र की घोर विफलता को भी उजागर किया है, यह भी जाहिर किया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एवं प्रशासन की जड़ों में भ्रष्टता एवं अराजकता तीव्रता से व्याप्त है, किसी बड़े क्रांतिकारी सफाई अभियान एवं सख्त उपायों से ही उनमें बदलाव लाया जा सकता है। भले ही अब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि हाथरस के सभी दोषियों के लिए कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है। हाथरस कांड की विडम्बना एवं वीभत्सता यह है कि कुछ लोग बाकायदा एक मंच का बैनर लेकर आरोपियों को बचाने की कोशिश करते नजर आए। यह घटना सीधे तौर पर बताती है कि निर्भया कांड के बाद जो भी कदम उठाए गए, वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नाकाफी साबित हुए हैं।

हाथरस प्रकरण से एक बार फिर अनेक सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर कितनी बालिकाएं, कब तक ऐसे जुल्मों का शिकार होती रहेंगी। कब तक अपनी मजबूरी का फायदा उठाने देती रहेंगी। दिन–प्रतिदिन देश के चेहरे पर लगती इस कालिख को कौन पोछेगा?

एक बड़ा सवाल यह भी है कि जांच और सजा के लिए बनाए गए लंबे–चौड़े तंत्र का संभावित अपराधियों में कोई खौफ क्यों नहीं दिख रहा है? दिल्ली के निर्भया मामले के बाद उमड़े जनाक्रोश के दबाव में जो बदलाव कानूनों में किए गए उनका भी समाज पर कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा। कुछ असर हुआ है तो सिर्फ इतना कि बलात्कार के जघन्य मामलों में अपराधियों को तुरत–फुरत मृत्युदंड देने की मांग हर संभव मंच से उठने लगी है।

इसका नतीजा हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ के रूप में देखने को मिला, जहां बलात्कार के संदिग्ध अपराधियों को उससे भी ज्यादा संदिग्ध ढंग से मौत के घाट उतार दिया गया। अपराधियों को अदालत से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, जिसके लिए न समाज में कोई आग्रह दिखता है, न सरकारी तंत्र में। युवती दलित पृष्ठभूमि से थी और गिरफ्तार चारों आरोपी उच्च जाति के हैं।

यही कारण है कि अपराधियों को दंडित करने की बजाय उनकी जाति और धर्म के आधार पर उनके बचाव में खड़े होने की प्रवृत्ति जरूर दिखने लगी है जो कठुआ रेप कांड के बाद अब हाथरस कांड में भी सामने आई है। ऐसी सोच के रहते क्या भारत कभी सभ्य समाज बन पाएगा? पुलिस–प्रशासन पर संदेह करने के अनेक कारण हैं, रात के अंधेरे में बिना पारिवारिक भागीदारी के पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? पुलिस एवं प्रशासन की मंशा एवं भूमिका पर सवाल ही सवाल हैं। उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश और मुख्यमंत्री योगी की तत्परता से इन सवालों के अधिक भरोसेमंद जवाब सामने आएंगे और ऐसी त्रासद घटनाओं पर नियंत्रण की दृष्टि से चेतना जगेगी।

हर बार की इस तरह की घिनौनी घटना सवाल तो खड़े करती हैं, लेकिन बिना उत्तर के वे सवाल वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। यह स्थिति हमारी कमजोर मानसिकता के साथ–साथ राजनीतिक विसंगतियों को भी दशार्ती है। शासन–व्यवस्था जब अपना राष्ट्रीय दायित्व नैतिकतापूर्ण नहीं निभा सके, तब सृजनशील शक्तियों का योगदान अधिक मूल्यवान साबित होता है। हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं हो रहा है, तभी बार–बार निर्भया, कठुआ एवं हाथरस जैसे कांड हमें झकझोर कर रख जाते हैं। हमारी सुसुप्तावस्था के कारण ही बलात्कार–व्यभिचार–गैंगरेप और बच्चियों के साथ भीषण यातनाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं बल्कि कड़े कानूनों की आड़ में निर्दोष लोगों को फंसाने का धंधा भी पनप रहा है। जिसमें असामाजिक तत्वों के साथ–साथ पुलिस भी नोट छाप रही है। हमें जीने के प्रदूषित एवं विकृत हो चुके तौर–तरीके ही नहीं बदलने हैं बल्कि उन कारणों की जड़ों को भी उखाड़ फेंकना है जिनके कारण से बार–बार नारी को जहर के घूंट पीने को विवश होना पड़ता है। जरूरत सख्ती बरतने की है, अगर बलात्कारियों के बच निकलने के रास्ते बंद करने के साथ ही उनको दिया जाने वाला दंड बाकी समाज के लिए एक कठोर सबक का काम करेगा तभी यह अपराधी मानसिकता के लोगों को ऐसे अपराध करने से रोकेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी वारदात नहीं रुक रही हैं, तो यह सोचना जरूरी है कि इस दिशा में और क्या किया जाए? इस समस्या का केवल कानून में समाधान खोजना भी एक भ्रांति है, समस्या के समाधान की दिशा में आधा–अधूरा प्रयत्न है। सबसे जरूरी है उन स्थितियों को खत्म करना, जो ऐसे अपराधों का कारण बनती हैं। बलात्कार जैसे अपराध कुंठित मानसिकता के लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कुंठाएं कई बार महिलाओं के प्रति हमारी सामाजिक सोच से उपजती हैं। महिलाओं को सिर्फ कानूनों में ही नहीं, सामाजिक धारणा के स्तर पर बराबरी का दर्जा देकर और उनकी सार्वजनिक सक्रियता बढ़ाकर ही इस मानसिकता को खत्म किया जा सकता है। इससे हम ऐसा समाज भी तैयार करेंगे, जो कुंठित मानसिकता वालों को बहिष्कृत कर सकेगा। प्रश्न यह भी है कि आखिर हमारे देश में महिलाओं को लेकर पुरुषों में ही इतनी कुंठाएं क्यों है? इन कुंठाओं को समाप्त कैसे किया जाये, इस पर भी तटस्थ चिन्तन जरूरी है।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
- EVENTS MANAGEMENT
- PR MANAGEMENT
- ARTISTS MANAGEMENT

http://www.takshakindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, अक्टूबर, 2020

अजीबो-गरीब : यदि सरकार कराए उच्च स्तरीय जांच तो उजागर होगा खेल

सौ रूपए के स्टांप पर करोड़ों की जमीन का हो जाता है करार

-उद्योग विहार (अक्टूबर 2020)-

गाजियाबाद। सावधान! यदि किसी कालोनाइजर से यदि आप भूखंड खरीद रहे है तो इससे पहले ये जान ले कि जिस कालोनी में आप भूखंड लेने जा रहे है, वह गाजियाबाद से स्वीकृत है अथवा नहीं। कहीं ऐसा न हो कि भूखंड खरीदने और उस पर आशियाना बनाने के बाद आपको पछताना पडे। जी हां देश की राजधानी दिल्ली सीमा से लगे गाजियाबाद में कई स्तरों पर जबरदस्त खेल चल रहा है। इसमें भी बडा खेल भू माफिया कर रहे है। भू माफिया जो अपने नाम से किसान से जमीन की खरीद ही नहीं करते है, बल्कि किसान से सौ रूपए कीमत के स्टापं पर करार कर लेते है। बाद में किसान से ही रजिस्ट्री कराते है।

बताते है कि सरकार यदि अधिकांश अनाधिकृत कालोनी से जुडे कागजातों को कब्जे में लेते हुए पडताल कराती है तो निश्चित तौर से चैकान्ने वाले तथ्यों का भंडाफोड होना तय है। पूर्व पार्षद ओम त्यागी के द्वारा रखे गए संवाददाता सम्मेलन के दौरान यहां तक उजागर हुआ कि गाजियाबाद में ऐसे भी लोग जमीन माफिया के तौर पर सक्रिय है जो कि किसान के

स्थान पर तहसील में किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर देते है तथा अटार्नी करा लेते है और इस अटार्नी के माध्यम से जमीन ही बेच दी जाती है। किसान की जमीन तो बेची जाती है, आड में सरकारी एलएमसी की जमीन को भी ठिकाने लगा दिया जाता है। सूत्र बताते है कि सत्ता से जुडे लोगों के द्वारा इस खेल को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है।

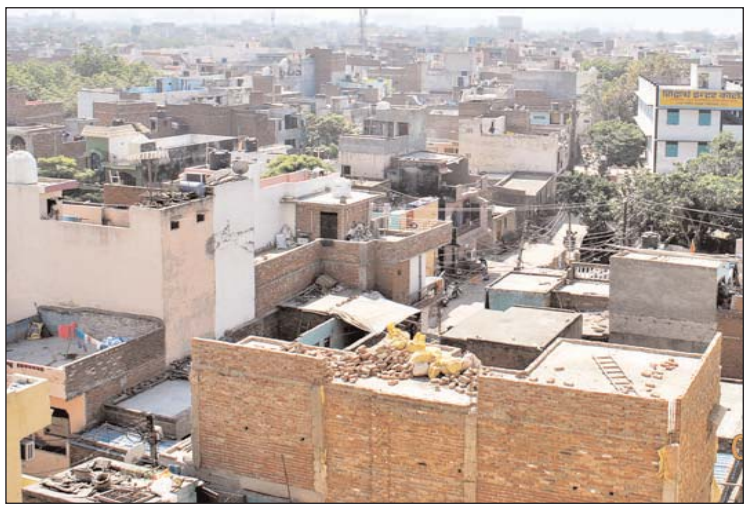

तहसील के रिकार्ड में इन लोगों का दूर तक भी कहीं नाम नहीं आता है। जब कभी तहसील के रिकार्ड की पडताल होती भी है तो उसमें किसान का ही नाम सामने आता है। अनाधिकृत कालोनी काटने वालों के लिए लाभ का सौदा इसलिए भी है कि उन्हें कालोनी काटने के दौरान

❑ अनाधिकृत कालोनी के इस खेल से सरकार हो रही करोड़ो की हानि

मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ज्यादा पैसा नहीं लगाना पडता है। इस खेल में तहसील के स्टाफ के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए के प्रवर्तन विभाग का स्टाफ भी पूरा साथ देता है।

चूंकि प्रत्येक तक तय हिस्सा पहुंचता है। नंद ग्राम से लगे शांति नगर में निगम की तोडफोड की कार्रवाई को लेकर विरोध की वजह भी यहीं है कि यदि सरकार पूरे प्रकरण को लेकर जांच बैठाती है तो अनेक चेहरे बेनकाब हो सकते है। जीडीए बोर्ड सदस्य चंद्र मोहन शर्मा कहते है कि अनाधिकृत कालोनी काटने वालों के साथ जीडीए के उन तमाम स्टाफ पर भी एक्शन होना चाहिए जिनके कार्यकाल के दौरान कालोनी काटी गई। जीडीए के स्टाफ पर एक्शन के बाद ही अनाधिकृत कालोनियों पर नियंत्रण संभव है।

काशीराम आवासीय योजना के आवंटन में धांधली उजागर

-उद्योग विहार (अक्टूबर 2020)-

गाजियाबाद। कांशीराम आवास योजना में अनियमितता से जुडी शिकायत की जांच डूडा के परियोजना अधिकारी पवन कुमार सौंपी। जांच में पाया गया कि आंवटित व्यकित की जगह फर्जीवाडा कर उस मकान में कोई ओर रह रहा है। सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा कर रहे रहे युवक के खिलाफ डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। ओर अन्य आवासो को लेकर भी टीम को जांच सौंपी गयी है। बता दे कि कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में आवास आवंटन के सम्बन्ध में डीएम को एक शिकायत प्राप्त हुई, डीएम ने प्रकरण की जाँच परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूड़ा) के पवन कुमार को सौंप दी।

जाँच में पाया कि प्रताप विहार (सिद्धार्थ विहार) के सैक्टर नौ में ब्लॉक-42के भवन संख्या-9/647 का आवटन महेन्द्र पुत्र भिखारी लाल निवासी कैलाशनगर के पक्ष में हुआ है, लेकिन मौके पर अरूण गोस्वामी पुत्र सतवीर गोसवामी नाम का व्यक्ति काबिज है, उसेआवंटन कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। आवटन पत्र पूर्णतः फर्जी निकला। धोखाधड़ी व सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कराने के इस प्रकरण में प्रकरण में डीएम के आदेश पर दोषी के विरूद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने डाला बिजली घरों पर डेरा, पुलिस तैनात

-उद्योग विहार (अक्टूबर 2020)-

गाजियाबाद। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के फैसले के खिलाफ मंगलवार को दूसरे दिन भी बिजली अफसरों, कर्मचारियों ने राजनगर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। वहीं, सुबह बुलंदशहर प कविनगर इंडस्ट्रीयल एरिया, मसूरी-गुलावठी औद्योगिक एरिया, साहिबाबाद साईट-4 सहित दर्जनो इलाको की बत्ती गुल होने पर उनकी आपूर्ति दोपहर तक शुरू नही हो सकी। जबकि पुलिस-प्रशासन और पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन अपनी तैयारियो का दावा कर रहा हैं। इमरजेंसी प्लान के तहत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से बिजलीघरों के लिए स्टाफ की डिमांड कर ली गई है। बिजलीघरों पर पुलिस तैनात है। सुबह दस बजे से जिले के संयुक्त विधुत वितरण निगम यूनियन के आंदोलनकारी कर्मचारी राजनगर स्थित मुख्य अभियंता आर के राणा के कार्यालय पर पहुंचना शुरू हो गए।

संयोजक आलोक त्रिपाठी, अवधेश कुमार, ओपी तेवतिया, भुवनेश तिवारी के नेतृत्व में एसडीओ, जेईईई सहित कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर नारेबाजी की। धरनारत कर्मचारियों ने कहा कि यदि मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन तेज करेंगे। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन जारी रहेगा। इधर, जिले के प्रमुख औद्योगिक एरिया में आपूर्ति ठप्प होने तथा आवासीय इलाको में आपूर्ति गडबड हो जाने पर कोई अधिकारी से लेकर कर्मचारी ने सुनवाई नही की। डीएम अजयशंकर पांडे, एडीएम सिटी

सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज, बुलाई ऊर्जा विभाग की बैठक

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में दखल देने का फैसला लिया लखनऊ। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को घाटे से उबारने के लिए निजी हाथ में सौंपने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ बिजलीकर्मियों की घोषित अनिश्चिकालीन हड़ताल को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक तलब कर ली है। इसको लेकर सीएम नेअपने कार्यालय में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

❑ राजनगर कार्यालय पर कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों ने डाला डेरा

❑ कविनगर, बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रीयल एरिया सहित दर्जनो इलाको में आपूर्ति ठप्प, लोग परेशान

शैलेंद्र कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन के साथ ही तीनो तहसीलो के अधिकारियों ने बिजली घरों की व्यवस्था परखी। साथ ही उच्चक्षमता के बिजली घरों पर पुलिस बल तैनात रखा गया। पश्चिमांचल के एमडी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वह जिलाधिकारियों के साथ वार्ता कर अपनी तैयारियां पूरी रखें। इमरजेंसी स्थिति के लिए कर्मचारियों की तैयारी रखें।

संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनीं जनता की समस्या

-उद्योग विहार (अक्टूबर 2020)-

गाजियाबाद। संपूर्ण समाधान दिवस पर नेहरूनगर स्थित सामुदायिक केंद्र पर डीएम अजयशंकर पांडे ने लोगो की समस्याओं को सुना। इस मौके पर डीएम ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगो को जागरूक किया। समाज कल्याण विभाग व भगीरथ सेवा संस्थान की ओर से आये युवाओं ने इस मौके पर नुक्कड नाटक की प्रस्तुति देकर लोगो को नशे से दूर रहने के लिये प्रेरित किया। प्रचार प्रसार के लिये पम्पलेट भी वितरित किये। समाधान दिवस के मौके पर दोपहर तक 30 सेअधिक शिकायते आई। डीएम ने इन शिकायतो का निस्तारण समयबद्ध किये जाने को कहा।

इस मौके पर सीडीओ अस्मिता लाल, एसडीएम सदर आदित्य प्रजापति, जिला समाज कल्याण अधिकारी एस के व्यास, डीपीआरओ अनिल त्रिपाठी, डीडीओ भालचंद्र त्रिपाठी सहित अनेको अधिकारी थे। वही दूसरी ओर मोदीनगर तहसील दिवस पर एसडीएम सौम्या पांडे, तहसीलदार उमाकांत तिवारी के समक्ष राजस्व विभाग, पालिका प्रशासन, पुलिस विभाग से जुडी शिकायते आई।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक "सत्येन्द्र सिंह" द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह